विचार बिन्दु

एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। न वह टूटता है और न उसमें रहने वाला कभी दुःखी होता है। –अज्ञात

भारत का युवा: अवसर की खिड़की या बेचैनी का विस्फोट?

भारत को अक्सर दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है। यह वाक्य हमारे सार्वजनिक जीवन में एक ऐसे मंत्र की तरह दोहराया जाता है मानो इससे अपने आप हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन केवल युवा आबादी होना किसी देश की सफलता की गारंटी नहीं होता। इतिहास में ऐसे कई समाज हुए हैं जिनके पास युवा ऊर्जा तो बहुत थी, पर दिशा नहीं थी–और तब वही ऊर्जा बेचैनी और असंतोष में बदल गई।

आज भारत भी लगभग उसी दोराहे पर खड़ा दिखाई देता है।

भारत की लगभग पैंसठ प्रतिशत आबादीपैंतीसवर्ष से कम आयु की है और लगभग पचास प्रतिशत आबादी पच्चीस वर्ष से कम आयु की है। यह भी कि भारत में कामकाजी आबादी 2044 तक बढ़ती रहेगी। अर्थशास्त्री इसे डेमोग्राफिकडिविडेंड यानी जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। सरल शब्दों में इसका अर्थ यह है कि यदि बड़ी संख्या में युवा काम करने की स्थिति में हों, तो वे किसी भी अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ग़ौर तलब बात यह है कि यह लाभांश किसी बैंक खाते की तरह अपने आप नहीं मिलता। उसके लिए शिक्षा, कौशल और रोजगार की ऐसी व्यवस्था वांछित होती है जो इस ऊर्जा को उत्पादक शक्ति में बदल सके। उल्लेखनीय है कि हम हर साल सात–आठ मिलियन नए रोज़गार सृजित करेंगे तभी हमारी युवा आबादी बारोज़गार होगी। यहीं यह भी याद कर लिया जाए कि वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में 15–29 वर्ष के युवाओं में बेरोज़गारी की दर 13.8 प्रतिशत है। अंतरराष्ट्रीय अनुमान यह दर 16 प्रतिशत बताते हैं।

यहीं से भारत की कहानी थोड़ी जटिल हो जाती है। देखा जाना चाहिए कि क्या हम इतनी बड़ी आबादी को रोज़गार देने की स्थिति में हैं? क्या हम इस राह पर हैं? क्या हम इस राह पर थोड़ा भी आगे बढ़े हैं?

पिछले दो दशकों में भारत में शिक्षा का विस्तार अभूतपूर्व रहा है। अगर मैं हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए उस वक्तव्य को याद न भी करूं जिसमें उन्होंने देश में हर रोज़ नए कॉलेज और हर सप्ताह नया विश्वविद्यालय खुलने की बात कही थी, यह एक यथार्थ है कि छोटे कस्बों तक कॉलेज पहुँच गए हैं, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है और हर साल लाखों छात्र वहां से डिग्रियाँ लेकर निकल रहे हैं। यह संख्यात्मक विस्तार हमें आह्लादित करता है। लेकिन इस विस्तार के साथ एक विचित्र विडंबना भी पैदा हुई है–डिठियों की संख्या तो बढ़ी है, पर उन डिग्रियों की गुणवत्ता प्रश्नों के घेरे में क़ैद है। जब भी दुनिया के श्रेष्ठ शैक्षिक संस्थानों की कोई सूची निकलती है, हम उस सूची में अपने देश के संस्थानों के नाम ढूंढते रह जाते हैं। और चलिए कोई बात नहीं कि हमारे शैक्षिक संस्थान दुनिया के श्रेष्ठतम में शुमार नहीं हैं, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इनमें से अधिकांश बदहाली के दौर से गुज़र रहे हैं। इनके पास न तो पर्याप्त शिक्षक हैं, न पुस्तकालय और न ऐसा सोच जो इनमें दी जा रही शिक्षा को प्रासंगिक बनाए रखे और यहां से डिग्री पाकर बाहर निकलने वाले युवाओं को रोज़गार दिला सके। विभिन्न आकलनों के अनुसार भारत के लगभग इक्यावन प्रतिशत स्नातक ही रोज़गार पाने की काबिलियत रखते हैं। मतलब बहुत साफ़ है। हमारे करीब आधे स्नातक तो रोज़गार पाने के काबिल ही नहीं हैं। कोढ़ में खाज यह कि रोज़गार के अवसरों की दुनिया भी अपेक्षित तेज़ी से नहीं फैली है। परिणाम यह कि आज भारत में लाखों ऐसे युवा हैं जिनके पास डिग्री तो है, पर नौकरी नहीं है। और न वे इस काबिल हैं कि कोई उन्हें नौकरी दे। यह स्थिति केवल आर्थिक समस्या नहीं है; यह एक सामाजिक मनोदशा भी पैदा करती है।

जब पढ़ा–लिखा युवा अपने भविष्य को अनिश्चित देखता है, तो उसके भीतर धीरे–धीरे एक मौन असंतोष जमा होने लगता है। इस असंतोष का एक अनोखा दृश्य देश के प्रतियोगी परीक्षा केंद्रों में दिखाई देता है। रेलवे, बैंक, राज्य सेवा, केंद्रीय सेवा–हर परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं। एक पद के लिए सैकड़ों या हजारों उम्मीदवारों की भीड़ खड़ी रहती है। जितनी योग्यता किसी पद विशेष के लिए अपेक्षित होती है उससे बहुत ज़्यादा योग्यता वाले युवा भी उस पद के आकांक्षी होते हैं। अगर ऐसे किसी युवा को वह नौकरी मिल भी जाती है तो वह कुण्ठित रहता है कि उसके पास अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी नहीं है। इसके अलावा परीक्षा होती है, परिणाम आता है, फिर किसी कारण से प्रक्रिया रुक जाती है, फिर नई परीक्षा की घोषणा होती है। इस बीच वर्षों बीत जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था ने भारतीय समाज में एक नया वर्ग पैदा कर दिया है–परीक्षा–जीवी युवा। देश के कई शहर–कोटा, प्रयागराज, पटना, दिल्ली का मुखर्जी नगर–आज ऐसे युवाओं की प्रतीक्षा और परिश्रम के अजीब मिश्रण से भरे हुए हैं। उनकी ज़िंदगी का सबसे ऊर्जावान समय एक अनिश्चित प्रतीक्षा में गुजर जाता है।

तकनीक, डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप संस्कृति ने युवाओं के लिए कुछ नई राहें भी खोली हैं। कई युवा उद्यमियों ने अपनी कल्पना और साहस से नए उद्योग खड़े किए हैं।भारत जैसे विशाल समाज में करोड़ों युवाओं की ऊर्जा को दिशा देने के लिए इससे कहीं व्यापक और गहरी व्यवस्था की आवश्यकता है। हमारे युवा अभी भी कामकाज के नए क्षेत्रों से अनभिज्ञ हैं।

इस पूरी कहानी में एक नया अध्याय डिजिटल क्रांति ने जोड़ दिया है।

आज का युवा पहले की किसी भी पीढ़ी से अधिक जागरूक है। उसके हाथ में स्मार्टफोन है और उसकी आँखों के सामने पूरी दुनिया है। वह देखता है कि दुनिया के दूसरे देशों में उसके समकालीन किस तरह अवसर पा रहे हैं, किस तरह अपने सपनों को आकार दे रहे हैं। यह तुलना स्वाभाविक रूप से आकांक्षाएँ बढ़ाती है। लेकिन जब आकांक्षाएँ तेज़ी से बढ़ें और अवसर धीमी गति से आएँ, तो बेचैनी पैदा होना लगभग अपरिहार्य हो जाता है।

राजनीति में भी युवाओं का नाम बहुत लिया जाता है। छात्र संघ चुनावों को युवाओं के लिए राजनीति के प्रवेश द्वार के रूप में प्रचारित किया जाता है। हर चुनाव में यह घोषणा सुनाई देती है कि युवा देश का भविष्य हैं। लेकिन यह भविष्य अक्सर भाषणों में ही दिखाई देता है। निर्णय लेने की वास्तविक संस्थाओं में युवाओं की भागीदारी भी सीमित ही है। युवाओं की ऊर्जा का उपयोग अधिकतर चुनावी प्रचार, सोशल मीडिया अभियानों या नारेबाज़ी में दिखाई देता है।

लेकिन यह भी सच है कि पूरी तस्वीर निराशा से भरी नहीं है।

तकनीक, डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप संस्कृति ने युवाओं के लिए कुछ नई राहें भी खोली हैं। कई युवा उद्यिमयों ने अपनी कल्पना और साहस से नए उद्योग खड़े किए हैं। लेकिन यह भी सच है कि ऐसे अवसर अभी भी सीमित दायरे में केंद्रित हैं। भारत जैसे विशाल समाज में करोड़ों युवाओं की ऊर्जा को दिशा देने के लिए इससे कहीं व्यापक और गहरी व्यवस्था की आवश्यकता है। हमारे युवा अभी भी कामकाज के नए क्षेत्रों से अनभिज्ञ हैं। कोटा जैसे कोचिंग केंद्रों का पनपना यह बताता है कि युवा अभी भी मेडिकल और इंजीनियरिंग से आगे नहीं सोच पा रहे हैं। मां–बाप के सपने भी सीमित हैं। हम ऐसा कोई तंत्र विकसित नहीं कर पाए हैं जो युवाओं को यह बता सके कि उनके सामने रोज़गार के अपरिमित मौके हैं, बशर्ते वे उसके लिए तैयार हों।

तो फिर सवाल वही है कि क्या भारत अपनी युवा आबादी को केवल एक सांख्यिकीय उपलब्धि मानकर संतुष्ट हो जाएगा, या उसे एक रचनात्मक शक्ति में बदलने का साहस करेगा? इसके लिए सबसे पहले शिक्षा को डिग्री उत्पादन की फैक्टरी बनने से रोकना होगा और उसे कौशल, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच से जोड़ना होगा। हमें प्रारम्भ से ही अपने युवाओं को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि उन्हें अपनी आजीविका के लिए नए–नए अवसर खोजने हैं। सरकारी नौकरी हरेक को नहीं मिल सकती है।

दूसरा, रोजगार सृजन को नीति का केंद्रीय लक्ष्य बनाना होगा–केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं, बल्कि उद्योग, सेवा क्षेत्र और उद्यमिता के विस्तार के माध्यम से। सबसे अहम बात यह कि हमें अपनी प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था में ही यह सोच शामिल करना होगा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और आप काम कहीं भी करें, उसमें निष्ठा और दक्षता ज़रूरी है। जब तक समाज में श्रम की महत्ता स्थापित नहीं होगी, हमारी समस्या बनी रहेगी।

और तीसरा, युवाओं को केवल भविष्य का नागरिक मानकर प्रतीक्षा में नहीं रखा जा सकता। उन्हें वर्तमान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी देनी होगी।

इतिहास में हर वह समाज आगे बढ़ा है जिसने अपनी युवा ऊर्जा को अवसर में बदलने की कला सीखी है।

भारत के सामने प्रश्न बहुत सीधा है, पर उसका उत्तर अत्यंत कठिन! क्या यह देश अपनी युवा शक्ति को भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बना पाएगा,या वह अनजाने में एक बेचैन पीढ़ी तैयार कर रहा है?

सच यह है कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी उसकी युवा आबादी है, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी है। युवा केवल संख्या नहीं होते, वे सपनों, आकांक्षाओं और अधीर उम्मीदों का संसार होते हैं। यदि उन सपनों को रास्ता मिलता है तो वही पीढ़ी राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताक़त बन जाती है; लेकिन यदि वे लगातार टलते रहें, तो वही ऊर्जा बेचैनी और असंतोष का रूप भी ले सकती है। इसलिए भारत के सामने असली प्रश्न जनसंख्या का नहीं, भविष्य का है–क्या यह देश अपनी युवा शक्ति को अवसर में बदलेगा, या उसे निराशा के हवाले कर देगा।

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल,
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

भारत अमेरिका व्यापार समझौता - आम आदमी, किसान, मजदूर की दृष्टि से

महावीर सिंह

भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौता यद्यपि पूरी तरह से अभी सामने नहीं आया किंतु मोटी सहमति जो मीडिया में, भारत के वो अमरीका के संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों ने साझा की है उस पर आधारित है यह लेख।

इस ट्रेड डील का अर्थ यों समझे कि अमेरिका भारत में कौन कौन सा सामान भेज पाएगा और भारत में प्रवेश पर उन वस्तुओं पर क्या टैक्स अर्थात टैरिफ लगेगा और भारत अमेरिकी बाजार में क्या उत्पाद किन टैक्स दरों पर बेच पाएगा।

इस समझौते का कई महीनों से इंतजार था, सब को, यानी सरकार, भारतीय उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों व दूसरे देशों को अपने अपने कारणों से इंतजार था। सरकार को भी इंतजार था और गैर सत्ता वाले राजनीतिक दलों को भी। सरकार को अपनी वाही वाही करवाने के लिए और विपक्षियों को सरकार की बखिया उधेड़ने के लिए। दूसरे देश इस बात का आंकलन करेंगे को उनके यहां के कौन कौन से उत्पादों पर भारतीय बाजार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और भारत से इस सिनेरियो में क्या माल आयात करना मुफीद रहेगा। भारत का किसान और दिहाड़ी मजदूर भी इसका इंतजार कर रहा था कि उसके दिन सही चलेंगे या उल्टे।

प्रथम दृष्टि में सरकार के अनुसार यह भारत के पक्ष में सर्वकालिक बढ़िया डील है और अमेरिका भी वाही वाही लूट रहा है अपने देश में और मुख्यत इस बात के लिए कि अमेरिका के किसानों और कृषि उत्पादों को भारत का 140 करोड़ उपभोक्ताओं वाला बाजार बिना टैरिफ के या न के बराबर टैरिफ पर। भारत के कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री व दूसरे आला लोगों का कहना है कि भारत के किसानों के हितों कोई प्रतिकूल प्रभाव न तो पड़ेगा और न पड़ने देंगे। वैसे सोचने वाली बात यह है कि इस से अलग वे कह भी क्या सकते हैं? मंत्रियों की मजबूरी होती है सरकार के फैसलों का ढोल बजाना।

आओ,कुछ मोटी मोटी बातों पर विचार करें। इस डील की भारतीय उद्योग संघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज यानी फिक्की में प्रतिक्रियाएं दी है । फिक्की के अनुसार शुल्क कम होंगे, रेगुलेटरी अड़चनें कम होंगी, नए अवसर खुलेंगे। उद्योग संघ का कहना है इस डील में नीतिगत तालमेल, नियम आधारित व्यापार के प्रति साझा प्रतिबद्धता है और विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। अधिकतर व्यापारिक व औद्योगिक संगठनों के द्वारा ऐसी प्रतिक्रियाएं देना आम बात है। आम लोग कहते है, इन संगठनों के पास ज्यादा कुछ कहने की कोई फ्रीडम भी नहीं होती। लेकिन यह बात भी सही है कि यह संगठन लगातार सरकार की नीतियों और व्यापार उद्योग पर उनके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की समीक्षा करते रहते है। इनके पास विस्तृत रूप से अनुसंधान करते रहने के लिए सारी आधारभूत सुविधाएं होती है। सरकारें इन की बातों पर ध्यान देती है क्योंकि अन्य ओर महत्वपूर्ण कारणों के अतिरिक्त सरकार से इनके डेटा आधारित वार्तालाप के कारण भी। किसानों व मजदूरों के कोई इस प्रकार के सशक्त संगठन नहीं जो लगातार सरकारी नीतियों पर विचार–विमर्श, अनुसंधान करके सरकारों को सावचेत करते रहें कि क्या उनके हित में, क्या अहित में है।

मैंने एक फार्मा सेक्टर के सेवा निवृत्त अधिकारी से यह जानना चाह कि अमेरिका में निर्यात होने वाली दवाओं पर 0 टैरिफ से इस सेक्टर को तो बहुत लाभ होगा। उनका कथन था यूएसए का फार्म सेक्टर पूर्णतः तबाह है, अमेरिका की मजबूरी है 0 टैरिफ पर भारतीय दवाइयों का आयात करना।अब भी 0 तारीफ पर ही आयात कर रहा है।कुछ समय के लिए कुछ डंडा दिखाने का प्रयास किया था किंतु चला नहीं। इसलिए इसमें कोई वाही वाही वाली बात नहीं है। ज्वेलरी व कीमती स्टोंस के बड़े व्यापारी से भी पूछा कि आप लोगों की तो बल्ले बल्ले है इस नई डील में।

उनका कहना था वैसे तो अधिकतर बड़े निर्यातकों ने 25 –50 प्रतिशत टैरिफ की काट निकाल ली थी। अपने दफ्तर ऐसे देशों में जहां पर इन चीजों पर कम शुल्क था, वहां स्थापित कर लिए थे और वहां से यूएसए में सामान भेजने पर, टैरिफ का असर बहुत कम हो जाता था। अब सब काम जीरो टैक्स पर यहीं से 100 प्रतिशत सही–सही होगा। फिर कुछ, रिलीफ तो है ही। ओर बहुत से आइटम्स है जिन पर 25–50 प्रतिशत के बजाए 18 प्रतिशत टैरिफ लगने से सुविधा तो होगी जैसे चमड़े का सामान, रेडीमेड कपड़े, आदि उद्योगों, व्यापारियों को।इन सेक्टर्स में कुछ रोजगार जो पहले कम हुए, पुनः खुल सकते है।

आइए, अब जरा कृषि सेक्टर पर भी बात कर लें।

भारत सरकार की अब तक की नीति रही है कि भारत के कृषि सेक्टर को निर्बाध आयात के लिए नहीं खोला जाएगा। यद्यिप 18 अगस्त 2025 से 31 दिसंबर 2025 की समयावधि में अमेरिकन कपास को 0 प्रतिशत आयात शुल्क पर भारत में आने की इजाजत इस डील से पहले दी थी किंतु अब इस डील से पहले वाला टैरिफ 11 प्रतिशत भारत वसूल कर रहा था।

■ इस समझौते से भारतीय कृषि उत्पादों (जैसे मसाले, चाय, कॉफी, नारियल तेल) पर अमेरिकी टैरिफ कम होगा, जिससे कुछ, अत्यंत सीमित संख्या में, किसानों को फायदा हो सकता है। यद्यपि सरकार दवा कर रही है कि आयात कोटा आधारित होगा अर्थात केवल एक निश्चित मात्रा तक ही आयात होगा

इस नई डील से अमेरिकन लंबे रेशे वाली कपास की एक निश्चित मात्रा में अत्यंत कम अथवा जीरो ड्यूटी पर आयात की संभावना है। इसका भारतीय कपास के बाजार मूल्य पर क्या प्रतिकूल प्रभाव होगा,यह आने वाला समय बताएगा किंतु सोचने वाली बात यह भी है कि क्या लंबी अवधि में भारतीय कपास का यह अमेरिकन कपास का स्थान तो नहीं ले लेगा?

आमतौर पर यह माना जा रहा है कि वस्त्र उद्योग जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है,उस पर निश्चित ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यूएस–बांग्लादेश डील में कुछ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स (खासकर यूएस कॉटन से बने) पर जीरो या बहुत कम टैरिफ है और भारत पर 18 प्रतिशत टैरिफ रह गया। इससे 100 प्रतिशत कॉटन प्रोडक्ट्स में भारत की प्रतिस्पर्धा कमजोर पड़ सकती है।बांग्लादेश अब न्यूनतम टैरिफ पर यूएस कॉटन इंपोर्ट करके सस्ते प्रोडक्ट्स बना सकता है, जिससे भारतीय कॉटन यार्न एक्सपोर्ट्स (बांग्लादेश को) घट सकते हैं।

भारत–अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के अनुसार अमेरिकी सोयाबीन तेल पर भारत आयात शुल्क (टैरिफ) को पूरी तरह खत्म या कम करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते से भारत में सोयाबीन तेल जीरो प्रतिशत ड्यूटी पर भारत में आ सकेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है और सोयाबीन तेल इसका बड़ा हिस्सा है। इसका प्रभाव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकते है । वर्तमान में क्रूड सोयाबीन तेल पर 16.5 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक ड्यूटी है । समझौते में इसे जीरो या कम करने की बात है। सरकारी कहना है कि यह आयात टैरिफ–रेट कोटा (टीआरक्यू) के तहत होगा, यानी एक निश्चित मात्रा तक ही छूट होगी, उसके बाद नॉर्मल ड्यूटी।

सोयाबीन तेल को समझौते में शामिल करने से अमेरिकी किसानों को तो निश्चित ही फायदा है लेकिन भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। 2024–25 में अमेरिकी सोयाबीन तेल निर्यात में 304 प्रतिशत वृद्धि हुई है। समझौते से यह और बढ़ेगा, जो घरेलू उत्पादन को प्रभावित करेगा।

भारत के बाजार में सोयाबीन के भाव गिर सकते है। इस दृष्टि से किसानों पर सकारात्मक प्रभाव सीमित हैं और नुकसान की भी संभावना है।

सरकारी मानना है कि इस से उपभोक्ताओं और इंडस्ट्री को फायदा, अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को भी। सस्ता आयातित सोयाबीन तेल से खाद्य तेल की कीमतें कम होंगी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स इंडस्ट्री को सस्ता कच्चा माल मिल सकता है, रोजगार बढ़ सकता है।

समझौते में पोल्ट्री और पशुपालन सेक्टर से संबंधी बातों में, अमरीका को डीडीजीएस (डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स) और ज्वार जैसे पशु चारे पर भी 0 प्रतिशत अथवा कम टैरिफ पर निर्यात की छूट मिलनी है । माना कि अगर सस्ते पशु आहार से पशुपालन सस्ता होता है, तो डेयरी किसानों को फायदा हो सकता है। सोयाबीन से तेल निकालने के बाद बचा सोया मील पशुओं के लिए,मुर्गी पालन के लिए, फिशरीज के लिए अत्यंत पौष्टिक फीड माना जाता है।इस से सोयाबीन किसान को सोय मील बेचने का वैकल्पिक बाजार मिल सकता है, ऐसा सरकारी दृष्टि कोण है किंतु किसान जानते है यह सोया मील फैक्ट्री वाला ही बेचता है। किसान को शायद इस से कोई फायदा हो, ऐसा मेरा मानना है।

अमेरिका में सोयाबीन मुख्य रूप से जीएम है, और किसान संगठनों का कहना है कि आयात से जीएम उत्पाद भारत में घुस सकते हैं, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जोखिम है। भारत में जीएम फसलों पर प्रतिबंध है।

इस समझौते से भारतीय कृषि उत्पादों (जैसे मसाले, चाय, कॉफी, नारियल तेल) पर अमेरिकी टैरिफ कम होगा, जिससे कुछ, अत्यंत सीमित संख्या में, किसानों को फायदा हो सकता है। यद्यपि सरकार दवा कर रही है कि आयात कोटा आधारित होगा अर्थात केवल एक निश्चित मात्रा तक ही आयात होगा। कोई भी आइटम जो भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचाए, वह समझौते में शामिल नहीं है। संवेदनशील उत्पादों जैसे डेयरी, मांस, मक्का, सोयाबीन (पूरा बीज), जीएम फसलें पर कोई छूट नहीं। सरकार का दावा है कि कृषि, डेयरी आदि उत्पादों का निर्यात बढ़ने से किसानों को फायदा देगा। किंतु यदि इनका अनलिमिटेड आयात होगा है तो किसानों को फसलें बदलनी पड़ सकती है। नुकसान भी होगा।

आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ (बीकेएस), एसकेएम, ऑल इंडिया किसान सभा ने विरोध किया। उनके अनुसार यह समझौता "अमेरिकी दबाव में आत्मसमर्पण" है, और लाखों किसानों की आजीविका खतरे में है। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने इसे 'धोखा' कहा, और कहा कि यह सोयाबीन, मक्का, कपास आदि पर प्रभाव डालेगा। पहले से ही कम एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) और बाजार अस्थिरता से परेशान किसान ओर प्रभावित होंगे।

कुल मिलाकर नकारात्मक प्रभाव ज्यादा लगते है, क्योंकि बढ़ते आयात से भारत में कृषि उत्पादों की कीमतें गिर सकती हैं। किसानों की आय प्रभावित होगी। लेकिन अगर सख्ती से लागू होता है, तो नुकसान सीमित रह सकता है। सरकार को बढ़ाने, फसल विविधीकरण और किसान सहायता की जरूरत होगी।

ओर आइए इस डील के उन भागों पर भी थोड़ी चर्चा करलें जो बेहद आपत्ति जनक लगते है ---

गत वर्ष तक भारत की वस्तुओं का अमेरिका में टैरिफ 3.3 प्रतिशत था यूएस ने इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया और अब कुछ शर्तों के साथ 18 प्रतिशत कर दिया!

यह कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, यद्यपि अभी सरकार की ओर से स्पष्टता का अभाव है।अमेरिका को यह अधिकार कैसे हो सकता कि वह यह तय करे के भारत किस से क्या खरीदेगा और किस से नहीं???? आज रूस, कल कोई ओर देश के लिए, अन्य किसी वस्तु के लिए ऐसा फरमान जारी होने का क्या अर्थ समझें?? रूस और ईरान से तेल नहीं खरीदने का अर्थ मोटे तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार!!!!!

यह कि अमेरिका के एक मंत्रियों अधिकारियों का समूह लगातार यह समीक्षा करेगा कि भारत समझौते का पालना कर रहा है या नहीं?? माना यह अधिकार है किसी भी देश को है कि वह अपने देश हित में समझौतों की सही सही पालना सुनिश्चित करावे किंतु किसी समझौते में लिखना कतई उचित नहीं।यह एक धमकी जैसा है, किसी भी समय कोई भी आधार बनाकर डील निरस्त करने और मन मर्जी के टैरिफ फिर लगाने की ।

ओर यह भी कि सामान्यत इस प्रकार की ज्वाइंट घोषणाएं दो देशों के मंत्री या आला अधिकारियों की उपस्थिति में होते है। इसकी घोषणा पहले यूएसए ने की फिर भारत के वाणिज्य मंत्री में प्रेस कॉफ्रेंस में इसके बारे में बताया। ऐसा कम ही सुना गया था, होंगे इसके भी कारण सरकार के पास। खैर हर आदमी की अपनी अपनी सोच किंतु यह जो कि भारत द्वारा किस देश से क्या खरीदा जाएगा, क्या नहीं, इसका फैसला दूसरा देश लेगा तो यह हमारी संप्रभुता पर सीधा सीधा प्रहार है। नव उपनिवेशवाद शुरू, नहीं???

–महावीर सिंह, पूर्व आईएएस

"हे विश्व के मानवों ! राष्ट्रवादी और फासिस्ट दृष्टिकोण के शासकों से सावधान !!"

मदन सिंह काला

वर्तमान युग वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी का है। पुराने वैज्ञानिक अनुसंधान गलत सिद्ध हो रहे हैं और नित नये अनुसंधान हो रहे हैं। आदमी की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव मस्तिष्क प्राकृतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए यथा हवा, पानी आदि भौतिक संसाधनों के उपयोग की दिशा में तेजी से चौकाने वाले अनुसंधान करने में संलग्न है। राजनैतिक लोग अपने ही राष्ट्र को महान सिद्ध करने के सिद्धांत राष्ट्रवाद के नाम पर अपने लोगों को राष्ट्र पर न्यौछावर कर देने का माहौल बनाते हैं। इस हेतु वे प्राचीन वैश्विक विधाओं यथा युद्ध, धर्म और बीमारी से उत्पन्न परिस्थितियों में अपने राष्ट्र को श्रेष्ठतम सिद्ध करने के वक्तव्य देते हैं। जनता को राष्ट्रवाद की आग में झोंककर अपने व्यक्तिगत हितों को साधने का प्रयास करते हैं। जबकि वर्तमान वैज्ञानिक युग में हम आमजनों को यह समझ आ जाना चाहिए कि यह दुनिया इस तरह की क्यों बनी हुई है।

युद्ध शांति के बारे में नहीं है – यह एक व्यवसाय है। सरकारें इस हेतु भारी मात्रा में जनता से वसूले टेक्स के धन का दुरुपयोग करते हैं। युद्ध सामग्री अनेक देशों की कंपनियां सप्लाई करती हैं। मीडिया युद्ध भेरी बजाकर शांतिप्रिय जनता को भी जोश में ले आता है। और युद्ध में राष्ट्रवाद के नाम पर सैनिक मारे जाते हैं। लड़ाकू देशों की कंपनियों को भारी आर्थिक लाभ होता है जबकि देश खून से लथपथ हो रहा होता है। इस प्रकार हर युद्ध शासनाधिकारियों के लिए एक लाभकारी अवसर बन जाता है।

धर्म हमेशा गॉड के बारे में नहीं होता है। इसके द्वारा डर पैदा किया जाकर लोगों को मानसिक रोगी बनाया जाता है। उन मानसिक रोगियों से जीवन को सुखद एवं सुरक्षित बनाने का चमत्कार गठित करवाने का स्वप्न दिखाकर, राजनैतिक संरक्षण प्राप्त धार्मिक लोग उन मासूम लोगों से उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा उन्हें मजबूर कर हड़प लिया जाता है। इससे लोगों को गरीबी के जाल में फंसाकर वे धार्मिक नेता अपने विशाल इम्पायर बना रहे हैं। इस प्रकार धार्मिकता की अपुष्ट धारणाएं साधारण बुद्धि के लोगों को धर्मभीरू बनाये रखने में सफल हो जाती हैं।

आम आदमी को अंधविश्वास, पाखंड और चमत्कार के चकाचौंध के दुष्प्रचार से गरीब रखे जाने का षडयंत्र वर्षों से चला आ रहा है। यहां तक कि अब तो मोक्ष अर्थात मुक्ति भी एक पेड सर्विस सी बन गई है।

वर्तमान समय में कोई भी बीमारी क्यों न हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में संलग्न राजनैतिक संरक्षण प्राप्त व्यवसायियों के लिए तो रोज सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसी बन जाती हैं। इलाज ढूंढना इन व्यवसायियों के लिए लाभदायक नहीं होता है। इसलिए वे यह नहीं चाहते कि मरीज मरें – वे बस यह चाहते हैं कि बीमार व्यक्ति बजाए स्वस्थ होने के, जीवन भर दवाइयां लेता रहे और उनका व्यवसाय पनपता रहे। पहले वे आमजन को बीमारी के विज्ञापनों के माध्यम से डर बेचते है और फिर वे दवाई के रूप में राहत बेचते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनियां बीमारियों का इलाज ढूंढने के बजाए उन्हें मैनेज करने की दवाइयों से ज्यादा पैसा कमाती हैं। अब हेल्थकेयर एक मार्केटप्लेस है। और आम बीमार उनका कस्टमर हैं।

इस प्रकार से अब हम यह समझ सकते हैं कि युद्ध आमजन को डराए रखता है। धर्म आमजन को आज्ञाकारी बनाये रखता है। बीमारी आम आदमी को दवाइयों पर निर्भर रखती है।– राजनेताओं ने उनके संरक्षण में रहने वाले लोगों से साझेदारी का संबंध रख, इस अमानवीय अराजकता को राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक विरासत और इतिहास की दुहाई का रूप दे दिया है और अब यह एक सिस्टम बन गया है। और यह ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसे इसे डिज़ाइन किया गया था।

अतः इस वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय युग में, आम आदमी को जब सब प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं और सूचना तो वह शक्ति है, जिससे आदमी की सुषुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में आमजन को चाहिए कि वे किसी भी देश के नागरिक क्यों न हों, इस धोखेबाज सिस्टम को नकारने के लिए उपलब्ध सूचनाओं का विवेकपूर्ण उपयोग कर मानव की भलाई व सुखद जीवन के निर्माण करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। मानव ही महान है।

–मदन सिंह काला,
सेवानिवृत्त आई ए एस

राशिफल

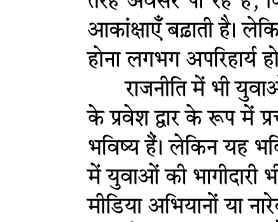

पंडित अनिल शर्मा

सोमवार 9 मार्च, 2026

चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठि तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2082, विशाखा नक्षत्र सायं 4:12 तक, व्याघात योग प्रातः 7:56 तक, गर करण दिन 10:20 तक, चन्द्रमा प्रातः 9:30 पर वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य–कुम्भ, चन्द्रमा–तुला, मंगल–कुम्भ, बुध–कुम्भ, गुरू–मिथुन, शुक्र–मीन, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह

आज यमघट योग और कुमार योग सूर्योदय से सायं 4:12 तक है। रवियोग सायं 4:12 से आरम्भ होगा। भद्रा रात्रि 11:28 से आरम्भ होगी। आज श्री एकनाथ षष्ठि है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 8:15 तक, शुभ 9:42 से 11:10 तक, चर 2:05 से 3:33 तक, लाभ–अमृत 3:33 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 6:47, सूर्यास्त 6:28

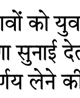

मेष

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है।

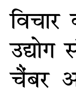

वृष

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल–आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

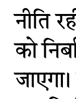

मिथुन

आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा।

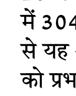

कर्क

आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा।

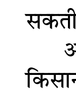

सिंह

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आज अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

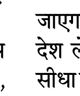

कन्या

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

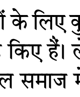

तुला

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

वृश्चिक

परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा, उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक कार्य के लिए यात्रा संभव है। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

घर–परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी। सुख–शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।